INDIAN STREAMS RESEARCH JOURNAL
ISSN NO : 2230-7850
IMPACT FACTOR : 5.1651 (UIF)
VOLUME - 15 | ISSUE - 4 | MAY – 2025

# "सतना जिले के आर्थिक व सामाजिक विकास में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का योगदान"

लवकुश हरिजन[1], डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्र[2]
[1]शोधार्थी भूगोल, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.).
[2] सहायक प्राध्यापक भूगोल, इन्द्रा स्मृति महाविद्यालय, न्यू रामनगर, सतना (म.प्र.).

**सारांश–**

सतना जिले के आर्थिक और सामाजिक विकास में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP) का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण परिवारों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए गए, जिससे उनकी आय में वृद्धि हुई और वे आर्थिक रूप से सशक्त बन रहे हैं। IRDP ने छोटे व्यवसाय, कृषि, पशुपालन और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की है, साथ ही इस योजना ने महिलाओं, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को प्राथमिकता देते हुए सामाजिक समानता और समावेशन को बढ़ावा दिया है। इससे ग्रामीण समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है। स्थानीय पंचायतों और स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी से विकास की प्रक्रिया अधिक समावेशी और प्रभावशाली बन रही है। कुल मिलाकर, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम ने सतना जिले में गरीबी उन्मूलन और सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

**मुख्य शब्द** – एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सतना जिला, ग्रामीण विकास, स्वरोजगार, आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक समानता।

## प्रस्तावना

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP) की शुरुआत भारत सरकार ने 1978 में की है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधार करना रहा है। यह कार्यक्रम उन्हें स्वरोजगार और स्थायी आजीविका के अवसर प्रदान करने पर केंद्रित है। यह एक महत्वाकांक्षी योजना रही है जो ग्रामीण गरीबी, बेरोजगारी और पिछड़ेपन की बहुआयामी समस्याओं को समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण से हल करने का प्रयास कर रही है। सतना जिला, जो मध्य प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है, मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र है जहां अधिकांश लोग कृषि और उससे जुड़े कार्यों पर निर्भर हैं। ऐतिहासिक रूप से इस जिले को व्यापक गरीबी, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, अविकसित बुनियादी ढांचे और सामाजिक असमानताओं जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। ऐसे परिप्रेक्ष्य में सतना जिले में प्क्च् के क्रियान्वयन ने जिले के ग्रामीण समुदाय की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में उल्लेखनीय परिवर्तन करने में सहायक बन रही है।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मूल उद्देश्य गरीब परिवारों को सब्सिडी और ऋण देकर छोटे व्यवसाय शुरू करने, कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प और अन्य आय–सृजन गतिविधियों में संलग्न होने के लिए

वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह आर्थिक सशक्तिकरण घर–घर की आय बढ़ाने, मजदूरी पर निर्भरता कम करने और हाशिए पर रहने वाले समाज के वर्गों में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। सतना एक कृषि प्रधान जिला है यहां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों की संख्या अधिक है, इसलिए इस समावेशी योजना से उन्हें व्यापक लाभ मिल रहा है। यह कार्यक्रम सबसे कमजोर वर्गों जैसे कि भूमिहीन मजदूरों, महिलाओं और सामाजिक रूप से वंचित समुदायों को चिन्हित करता है, जिससे सामाजिक समानता और सशक्तिकरण को प्रोत्साहन मिला है।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के आर्थिक प्रभावों को सतना जिले में ग्रामीण परिवारों की आय के स्रोतों में विविधता के माध्यम से देखा जा सकता है। इस योजना के पहले, अधिकांश परिवार खेती और मौसमी मजदूरी पर निर्भर थे, जिससे आर्थिक अनिश्चितता और निरंतर गरीबी बनी रहती थी। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों को क्रेडिट और कौशल विकास के अवसर प्राप्त हुए, जिससे कई लोगों ने दुग्ध उत्पादन, पोल्ट्री, वस्त्र बनाना, कुम्हार का काम और लघु व्यापार जैसे छोटे उद्यम स्थापित किए। इस विविधता ने ग्रामीण परिवारों को कृषि जोखिम जैसे सूखे और फसल असफलता से बचाव करने में सहायक रही है। साथ ही उद्यमशीलता में वृद्धि ने स्थानीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित किया है, रोजगार सृजन हुआ, खरीद क्षमता बढ़ी और बाजार से संबंध मजबूत हुई है। समय के साथ इससे जिले में जीवन स्तर और आर्थिक मजबूती में सुधार हुआ है।

सामाजिक दृष्टि से IRDP ने सतना में महिलाओं और वंचित समुदायों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस कार्यक्रम ने महिलाओं की भागीदारी को विशेष प्रोत्साहन दिया और लाभ का एक बड़ा हिस्सा महिलाओं के लिए सुरक्षित रखा है। इस पहल से महिलाओं को वित्तीय संसाधनों तक बेहतर पहुंच मिली और परिवार एवं समाज में उनकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ी। कई महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह बनाए और छोटे उद्यम शुरू किए, जिससे लैंगिक समानता और सामाजिक समावेशन को बल मिला है। अनुसूचित जाति और जनजाति समुदायों पर ध्यान केंद्रित करने से सामाजिक असमानताएं कम हुईं और ये समुदाय मुख्यधारा के विकास में सम्मिलित हो रही हैं। आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ने से शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं तक उनकी पहुंच बेहतर हुई, जिससे विकास और सशक्तिकरण का चक्र चल पड़ा।

संस्थागत दृष्टि से सतना में IRDP के क्रियान्वयन ने विभिन्न सरकारी विभागों, वित्तीय संस्थानों और स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के बीच मजबूत सहयोग स्थापित किया है। इस कार्यक्रम की सफलता पंचायतों, बैंकों, प्रशिक्षण केंद्रों और विस्तार सेवाओं के बीच समन्वय पर निर्भर है। यह बहु–हितधारक दृष्टिकोण सही लाभार्थियों की पहचान, तकनीकी सहायता प्रदान करने और प्रगति की निगरानी में मददगार साबित हो रही है। ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार प्रशिक्षण जैसे प्रशिक्षण कार्यक्रम प्क्च के साथ संचालित की जा रही है, जिनसे ग्रामीण युवाओं के कौशल और क्षमताएं बढ़ीं और वे अपने उद्यमों को स्थिर और बढ़ाने में सक्षम हुए हैं। इस तरह के संस्थागत सशक्तिकरण ने न केवल कार्यक्रम के क्रियान्वयन को बेहतर बनाया बल्कि जिले में मजबूत ग्रामीण विकास ढांचा भी तैयार किया है।

सतना में इस योजना को लागू करने, निगरानी और स्थिरता से जुड़े कई चुनौतियां भी सामने आई हैं। जैसे कि लाभार्थियों में जागरूकता की कमी, ऋण वितरण में देरी, बाजार तक सीमित पहुंच और परियोजना के बाद समर्थन का अभाव है। इसके अलावा कुछ अत्यंत कमजोर वर्ग प्रक्रियात्मक जटिलताओं और सामाजिक बाधाओं के कारण लाभ नहीं उठा सके। इन समस्याओं को दूर करने के लिए शासन में सुधार, क्षमता निर्माण और समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है। साथ ही प्क्च को अन्य ग्रामीण विकास पहलों के साथ समेकित करना और अधिक सहभागितात्मक व मांग आधारित दृष्टिकोण अपनाना इसके प्रभाव को और बेहतर कर सकता है।

## शोध का उद्देश्य –

शोध पत्र प्रारंभ करने से पूर्व यह निश्चिय करना परम आवश्यक होता है कि शोध से संबंधित सूचनाओं का गहन अध्ययन करना नवीन प्रश्नों का निर्माण, अवधारणाओं एवं समझ को विकसित करने हेतु तत्वों का पता लगाना तथा नवीन सम्भावनाओं को खोजना शोध कार्य का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। शोध की अवधारणा प्रत्येक क्षेत्र में होती है, जिससे प्रत्येक क्षेत्र को और अधिक सशक्त बनाया जा सके। अध्ययन का क्षेत्र तो बहुत

व्यापक है, परन्तु व्यापक क्षेत्र में ही शोध के निश्चित उद्देश्यों से संबंधित तथ्य ही एकत्र किये जायेंगे। प्रस्तावित शोध पत्र से संबंधित कुछ प्रमुख उद्देश्यों का निर्माण किया गया है, जो इस प्रकार है–

- सतना जिले के आर्थिक व सामाजिक विकास में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के योगदानों का अध्ययन करना।
- जिले के उद्यमों के विकास व विस्तार में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का योगदानों का मूल्यांकन करना।

उपरोक्त उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए शोध पत्र को वास्तविक मानकों के अनुरूप पूर्ण करने का सार्थक प्रयास किया गया है।

## शोध प्रविधि –

प्रस्तुत शोध पत्र में प्रयोग किये जाने वाले तथ्यों को प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों के माध्यम से एकत्रित किया गया है। जिसके लिए प्राथमिक समंकों के संकलन हेतु शोधार्थी द्वारा लोगों से व्यक्तिगत सम्पर्क कर अनुसूची के माध्यम से मौलिक समंकों को संकलित किया गया है। द्वितीयक समंकों का संकलन शासकीय एवं गैर शासकीय सूचनाओं, पत्र–पत्रिकाओं एवं प्रकाशनों इत्यादि से एकत्रित किये गये हैं। प्राथमिक समंकों को वर्गीकृत कर सारणीयन के पश्चात् विश्लेषणात्मक अध्ययन कर परिणाम प्राप्त किये गये हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में अवलोकन, सर्वेक्षण, निदर्शन, इत्यादि प्रविधियों का भी यथा सम्भव प्रयोग किया गया है।

## विश्लेषण –

अध्ययन क्षेत्र में सतना जिले के आर्थिक व सामाजिक विकास में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम से यहां के ग्रामीण अंचलों के विकास एवं व्यक्तियों के आर्थिक व सामाजिक दशाओं का मूल्यांकन करने हेतु सतना जिले से 300 उत्तरदाताओं का प्रत्यक्षतः दैव–निदर्शन प्रविधि के सविचार विधि का उपयोग कर चयन किया गया है और इस प्रकार चयनित उत्तरदाताओं से सम्पर्क स्थापित कर अनुसूची के माध्यम से प्राथमिक समंकों का संग्रहण किया गया है, जिन्हें सरल व बोधगम्य बनाने हेतु सारणीबद्ध किया गया। अतः मौलिक रूप में एकत्रित किये गये आकड़ों को निम्नानुसार प्रस्तुत कर विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है–

- **अध्ययन क्षेत्र के आर्थिक व सामाजिक विकास में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का योगदान** – सतना जिले के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का सराहनीय योगदान है या नहीं से संबंधित प्राथमिक आकड़ों को चयनित उत्तरदाताओं से सर्वेक्षण का मौलिक रूप में संकलित किया गया है, जिन्हें सरल व सुगम्य बनाने हेतु उन्हें वर्गीकरण के साथ सारणी क्रमांक 01 में प्रस्तुत कर विश्लेषणात्मक मूल्यांकन किया गया है, जो इस प्रकार है–

**सारणी क्रमांक 01**

**जिले के आर्थिक व सामाजिक विकास में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का योगदान**

| क्रमांक | विवरण | उत्तरदाताओं की संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का सराहनीय योगदान है | 272 | 77ण्33 |
| 2. | एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का सराहनीय योगदान नहीं है | 68 | 22ण्67 |
| कुल योग | | 300 | 100ण्00 |

स्रोत– व्यक्तिगत सर्वेक्षण।

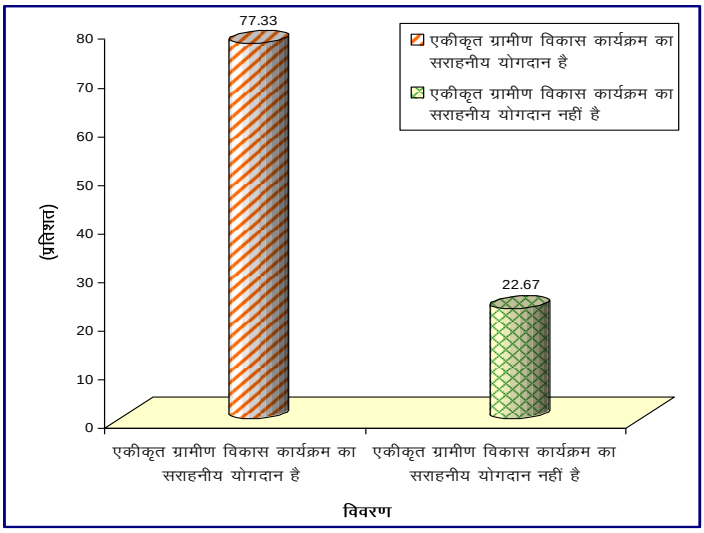


**आरेख क्रमांक 01 : जिले के आर्थिक व सामाजिक विकास में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का योगदान।**

उक्त सारणी क्रमांक 01 एवं आरेख के समंकों का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि जिले के आर्थिक व सामाजिक विकास में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के योगदान से संबंधित है। शोधार्थी द्वारा चयनित किये गये कुल 300 उत्तरदाताओं में से 232 उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का सराहनीय योगदान है, जिनका प्रतिशत 77.33 है जबकि वहीं 68 उत्तरदाताओं ने अपना अभिमत दिया कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का सराहनीय योगदान नहीं है जिनका प्रतिशत 22.67 है। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि जिले से चयनित किये गये सबसे अधिक 232 उत्तरदाताओं ने यह माना है कि जिले के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का सराहनीय योगदान है।

**जिले के उद्यमों के विकास व विस्तार में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का योगदान** – अध्ययन क्षेत्र के उद्यमों के विकास व विस्तार में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का योगदान है या नहीं से संबंधित वास्तविकता का आकलन करने के लिए जिले से चयनित किये गये उत्तरदाताओं से सर्वेक्षण कर मौलिक समंकों को साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से संकलित किया गया है, जिन्हें सरल व बोधगम्य बनाने हेतु वर्गीकृत कर सारणी क्रमांक 02 में प्रस्तुत कर विश्लेषणात्मक परीक्षण किया गया है–

**सारणी क्रमांक 02**
**अध्ययन क्षेत्र के उद्यमों के विकास व विस्तार में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का योगदान**

| क्रमांक | विवरण | उत्तरदाताओं की संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | उद्योगों के विकास व विस्तार में विकास कार्यक्रम का योगदान है | 222 | 74ण्00 |
| 2. | उद्योगों के विकास व विस्तार में विकास कार्यक्रम का योगदान नहीं है | 78 | 26ण्00 |
| कुल योग | | 300 | 100ण्00 |

स्रोत– प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित।

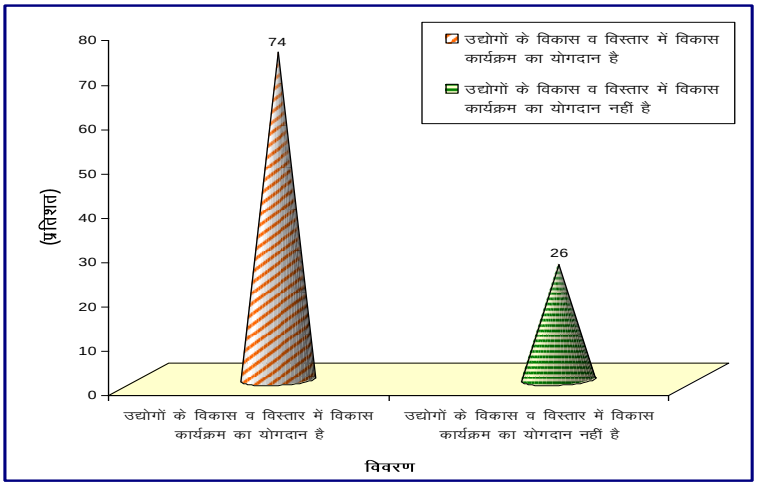


**आरेख क्रमांक 02 : अध्ययन क्षेत्र के उद्यमों के विकास व विस्तार में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का योगदान।**

उपरोक्त सारणी क्रमांक 02 एवं आरेख के समंकों से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र के उद्यमों के विकास व विस्तार में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के योगदान से संबंधित है। शोधार्थी द्वारा चयनित कुल 300 उत्तरदाताओं में से 222 उत्तरदाताओं ने यह स्वीकार किया है कि उद्योगों के विकास व विस्तार में विकास कार्यक्रम का योगदान है जिनका प्रतिशत 74.00 है। जबकि वहीं 78 उत्तरदाताओं का मानना है कि उद्योगों के विकास व विस्तार में विकास कार्यक्रम का योगदान नहीं है जिनका प्रतिशत 26.00 है। अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अध्ययन क्षेत्र के उद्योगों के विकास व विस्तार में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का महत्वपूर्ण योगदान है। अतएव चयनित सबसे अधिक उत्तरदाताओं ने यह स्वीकारा है कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिले के विकास में सकारात्मक योगदान अदा कर रहा है।

## निष्कर्ष –

शोध पत्र से संबंधित उपरोक्त प्राथमिक समंकों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने से सुस्पष्ट होता है कि सतना जिले के आर्थिक सशक्तिकरण में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का सराहनीय योगदान है। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन से ही अध्ययन क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित हो रहा है, जिसकी वजह से अध्ययन क्षेत्र के नागरिकों को रोजगार व स्वरोजगार के अवसर सुलभ हो रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों की प्रच्छन्न बेरोजगारी की दर में कमी आयी है जिससे सतना जिले के ग्रामीण नागरिकों की आय के स्तर में वृद्धि हुयी है और लोगों का सामाजिक जीवन समुन्नत हो रहा है, जिसका प्रभाव जिले व राज्य के अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक रूप में पड़ रहा है।

## संदर्भ –

1. दत्त, रुन्द्र एवं सुंदरम – भारतीय अर्थव्यवस्था, एस. चंद एण्ड कंपनी, नई दिल्ली, वर्ष 2022
2. मिश्रा, एस.के. एवं पुरी, वी.के. – भारतीय अर्थव्यवस्था : विकास और योजना, हिमालय पब्लिशिंग हाउस, मुंबई, वर्ष 2021
3. भारत सरकार – एकीकृत ग्रामीण विकास – दिशा–निर्देश और प्रदर्शन रिपोर्ट, ग्रामीण विकास मंत्रालयय, नई दिल्ली, वर्ष 2000
4. भारत का योजना आयोग – एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर मूल्यांकन अध्ययन, भारत सरकार, वर्ष 2021
5. श्रीवास्तव, एम.पी. – ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा, वर्ष 2018
6. विश्वनाथ, टी.आर. – ग्रामीण विकास : नीति एवं प्रशासन, नटराज पब्लिशर्स, देहरादून, वर्ष 2016
7. रामनाथन, डॉ. के.वी. – ग्रामीण भारत में गरीबी और विकास, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, वर्ष 2015